

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 1966 (पौष 10, 1888)

No. 53]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 1966 (PAUSA 10, 1888)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 14th दिसम्बर, 1966 तक प्रकाशित किये गये :—

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 14th December, 1966 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख Name and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
208	No. 152-ITC (PN)/66 dt. 12th Dec. 1966.	Min. of Commerce	Import of values, miniature ceramic condensers, R.F. Transistors and ferrite antenna rods by actual users for manufacture of radio receivers and transistors radio receivers April/66 March/67.
209	No. F. 4 (20) Tex. (D)/66 dt. 13-12-66. सं० फा० 4 (20)-टैक्स (डी)/66 दिनांक 13 दिसम्बर 1966	-do- वाणिज्य मंत्रालय	Constitution of a High Power Committee to go into the programmes of the mion export oriented agricultural commodities including raw jute, raw cotton, tea, tobacco and oil seeds. प्रमुख निर्यात अभिमुख कृषितम वस्तुओं के, जिसमें कच्चा जूट, कपास, चाय, तम्बाकू तथा तेलहन शामिल हैं, कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति गठित करने का निर्णय किया गया है।
210	No. RS/1/4/66-L. dt: 14-12-66 सं० आर० एम० 1/4/66-एल० दिनांक 14 दिसम्बर 1966	Rajya Sabha Secretariat राज्य सभा सचिवालय	Proroguing the Rajya Sabha. राज्य सभा का सत्रावसान

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय सूची (CONTENTS)

पृष्ठ (Pages)	पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 871	भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .. 77
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 1151	भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 769
	भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम —
	भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रश्न समितियों की रिपोर्टें

पृष्ठ (Pages)	पृष्ठ (Pages)
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	भाग III—खंड 2—एकसूच कार्यालय, नृपकृता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस .. 481
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं .. 167
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .. 1019
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ-लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .. 901	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस .. 249
	पृष्ठ सं० 53—
	24 दिसम्बर 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट .. 1855
	3 दिसम्बर 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े .. 1867
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 3625
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court)	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. 345
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India.
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta .. 481
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. 2325	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. 249
	SUPPLEMENT No. 53—
	Weekly Epidemiological Reports for week-ending 24th December 1966
	Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 3rd December 1966 .. 1867

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संघर्षों से संबंधित अधिवृत्तनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 1966

सं० 12/50/66-ई०-प्रापटी०—भारत रक्षा नियम, 1962 के नियम 133-बी० के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती हुई, केन्द्रीय सरकार यह आदेश देती है, कि (1) श्रीमती कुसुम बाई करीम सुपुत्री स्वर्गीय श्री हाजी मोहम्मद हाजी मूसा सैत तथा स्वर्गीय श्रीमती अमना बाई हाजी इस्सा, जो पट्टरगट्टी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) की भूतपूर्व निवासी थी और (2) श्रीमती जबैदा बाई उस्मान लतीफ, सुपुत्री स्वर्गीय श्री हाजी मोहम्मद हाजी मूसा सैत तथा स्वर्गीय श्रीमती अमना बाई हाजी इस्सा, जो स्नेल रोड, रानाबाव (गुजरात राज्य) की भूतपूर्व निवासी थी और दोनों अब कराची की पाकिस्तानी राष्ट्रिक हैं, की भारत में समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति जो कि उनकी है, उनके पास है या जिसका प्रबन्ध उनकी ओर से किया जाता है, भारत शत्रु सम्पत्ति परिरक्षक के अधिकार में निहित होगी।

बी० के० आहूजा,
संयुक्त सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय
(कृषि विभाग)

प्रस्ताव

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 1966

सं० 15-27/66-एल०डी०-1—हाल ही के वर्षों में भारत के मुर्गी पालन उद्योग ने तेजी से उन्नति की है। राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा व्यापक मुर्गी-पालन विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। गैर-सरकारी व्यवसाय ने भी इस क्षेत्र में काफी सहयोग दिया है। कुक्कुट-पदार्थों के पोषण सम्बन्धी बढ़ते हुए ज्ञान और सुरक्षित आहारों से भारतीय खुराक की अनुपूरकता की आवश्यकता अनुभव करते हुए इन पदार्थों की मांग बहुत बढ़ गई है। इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अच्छे जननिक गुणों वाले पक्षियों का बड़ी संख्या में उत्पादन करना और वैज्ञानिक तरीकों से उनका पालन-पोषण करना जरूरी है। इससे पर्याप्त विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। गैर-सरकारी और पब्लिक क्षेत्रों में देश में कुक्कुट-उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में क्रियान्वित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के मार्ग में जो समस्याएं आती हैं, उनको सुलझाने के लिए भारत सरकार ने एक केन्द्रीय कुक्कुट-पालन विकास सलाहकार परिषद् स्थापित करने का निर्णय लिया है :

2. इसके अनुसार परिषद् निम्नलिखित रूप से निर्मित की गई है :—

1. अध्यक्ष भारत सरकार के खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्री।
2. उपाध्यक्ष खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता उप-मंत्री पशु-पालन के इन्चार्ज।

3. सदस्य

1. भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव, पशु-पालन, के इन्चार्ज, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय।
2. भारत सरकार के पशु-पालन विकास आयुक्त।
3. भारत सरकार के पशु-धन विकास सलाहकार।
4. भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार।
5. भारत सरकार के पशु-पालन उपायुक्त (पशु स्वास्थ्य) खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय।
6. कुक्कुट विशेषज्ञ, विस्तार निदेशालय, भारत सरकार।
7. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि।
8. तकनीकी विकास के महा-निदेशालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि।
9. से
12. चार राज्यों, संघ क्षेत्रों से पशु-पालन के निदेशक अथवा मुख्य कुक्कुट विशेषज्ञ, प्रत्येक क्षेत्र से एक भारत सरकार द्वारा दो वर्ष के लिए बारी-बारी नामजद किया जाएगा।
13. उप-महा निदेशक (पशु विज्ञान) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्।
14. कुक्कुट अनुसन्धान प्रभाग के मुख्य, भारतीय पशु-पक्षिकरसा अनुसन्धान संस्थान, इज्जतनगर।
15. केन्द्रीय खाद्य तकनोलोजिकल अनुसन्धान संस्थान, मैसूर का एक प्रतिनिधि।
16. इंडियन स्टैंडर्ड इन्स्टीट्यूशन का एक प्रतिनिधि।

17. बड़े वाणिज्यिक निर्गमों से एक प्रतिनिधि ।

18. तथा

19. कुक्कुट उत्पादन से संबन्धित सहकारिता समितियों के दो प्रतिनिधि ।

20. से

23. चार गैर-सरकारी कुक्कुट से सम्बन्धित उन्नतिशील किसान, प्रत्येक क्षेत्र से एक ।

24. कुक्कुट से संबंधित उपकरण निर्माताओं से एक प्रतिनिधि ।

25. तथा

26. कुक्कुट-चारा निर्माताओं के दो प्रतिनिधि—बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के निर्माताओं का एक-एक प्रतिनिधि ।

क्रमांक संख्या 17 से 26 तक के सदस्य भारत सरकार द्वारा नामजद किये जायेंगे ।

4. सदस्य सचिव . पशु-पालन उपायुक्त (कुक्कुट), खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार ।

3. भारत सरकार समय-समय पर उन लोगों के अतिरिक्त सदस्य नामजद कर सकती है जिनका परिषद् में पहले ही प्रतिनिधित्व नहीं है ।

4. परिषद् एक सलाहकार निकाय होगी और निम्नलिखित कार्य करेगी :—

(1) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कुक्कुट पालन विकास कार्यक्रमों पर समय-समय पर विचार करना ।

(2) कुक्कुट-पालन विकास कार्यक्रमों की प्रगति पर पुनर्विचार और जहाँ आवश्यकता है वहाँ गति को तेज करने के उपायों की सिफारिश करना ।

(3) कुक्कुट प्रजनन, पोषण, रोग नियंत्रण, तकनालोजी, विपणन, व्यापार आदि समस्याओं पर जिनमें मूल्य नीति और सुधार सम्बन्धी सुझाव शामिल हैं पुनर्विचार करना ।

(4) अन्य कार्य जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा परिषद् को सौंपा जाए ।

5. परिषद् की बैठक आबधिक तौर पर उस समय और उस स्थान पर होगी जो अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए जायेंगे ।

6. परिषद् प्रस्ताव द्वारा ऐसी समितियां नियुक्त करेगी जो उसे कुक्कुट प्रजनन, चारा एवं विपणन, रोग नियंत्रण, उपकरण निर्माण तथा अन्य उपयुक्त कार्य सम्बन्धी समस्याओं के विषय में सलाह दे सके ।

आवेश

आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों के प्रशासन तथा भारत सरकार के मन्त्रालयों

के विभाग, योजना आयोग, मन्त्रिमण्डल, सचिवालय प्रधान मन्त्री सचिवालय, लोक-सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रस्ताव को भारत के गजट में प्रकाशित किया जाए ।

एस० जे० मजुमदार,
अतिरिक्त सचिव

परिवहन तथा विमानन मन्त्रालय

परिवहन तथा नौवहन विभाग

(परिवहन पक्ष)

पत्तन

नई दिल्ली, दिनांक-1 दिसम्बर 1966

संस्थाप

सं०-13-पी० जी० (66)/66—भारत सरकार को मदरास पत्तन की 1965-66 की प्रशासनिक रिपोर्ट मिल गई है । रिपोर्ट की मुख्य बातें ये हैं:—

1. वित्तीय स्थिति : विचाराधीन वर्ष में पोर्ट ट्रस्ट की वास्तविक कुल राजस्व प्राप्तियां 538.64 लाख रुपये की हुई । इसके विपरीत पिछले वर्ष यह राशि 444.77 लाख रुपये थी ।

वर्ष का कुल व्यय, ऋण प्रभार सहित, 436.20 लाख रुपये हुआ । पिछले वर्ष यह राशि 376.85 लाख रुपये थी । व्यय में वृद्धि मुख्यतः गोदी सिबन्दी और रेलवे विभाग के अन्तर्गत हुई ।

विचाराधीन वर्ष में पोर्ट ट्रस्ट ने 20 लाख रुपये की राशि अपने पूंजी खाते में, 37.74 लाख रुपये पुनर्नवन और पुनः पूंजीयन निधि में और एक लाख रुपये सामान्य बीमा निधि में अंशदान किये ;

कनहारी निधि की प्राप्तियां और व्यय क्रमशः 10.60 लाख और 11.98 लाख रुपये की रही । व्यय में 3 लाख रुपये की राजस्व खाते को अंशदान में दी हुई राशि भी शामिल है । इस तीन लाख रुपये की अंशदान में दी हुई राशि के अलावा कार्यक्रम के परिणाम 1.62 लाख रुपये का अधिशेष दिखाते हैं । 1965-66 के अन्त में खाते में 1.71 लाख रुपये का इतिशेष था ।

वर्ष के अन्त में विभिन्न आरक्षित निधियों में 3.16 करोड़ रुपये का शेष था । इसके अतिरिक्त राजस्व और कनहारी खाते में 102.26 लाख रुपये का इतिशेष था ।

वकाया ऋण :

(1) विचाराधीन वर्ष के अन्त तक वकाया के रूप में भारत सरकार को देय ऋण की सम्पूर्ण राशि 5.34 करोड़ रुपये थी ।

(2) वर्ष में पुनर्निर्माण और विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक 33.43 लाख रुपये की राशि निकाली गई, और इस प्रकार 31 मार्च, 1966 तक ली गई ऋण की कुल राशि 4.77 करोड़ रुपये हुई ।

2 यातायात :

वर्ष में पत्तन से आने जाने वाले व्यापार की मात्रा में सामान्य वृद्धि हुई । वर्ष में पत्तन से होकर जाने वाले आयात और निर्यात के कुल टन भार की संख्यायें क्रमशः 329879 और 1572713 हैं । पिछले वर्ष ये संख्यायें 2992865 टन (आयात) और 1405283 टन (निर्यात) थी । आयात में वृद्धि का कारण खाद्यान्नों रासायनिक खादों और फास्फेटों में तीव्र वृद्धि के कारण था । मशीनों, लोहा, और फौलाद तथा अन्य धातुओं के आयात में भी पर्याप्त वृद्धि हुई । कोयले के आयात में कमी के कारण इस वृद्धि में थोड़ी कमी आ गई । कच्चे लोहे, बंकर और मुलैस के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि के कारण वर्ष में निर्यात में भी वृद्धि हुई । कच्चे मैंगनीज के निर्यात में कमी के कारण इस वृद्धि में कुछ कमी पड़ गई ।

1965-66 के तटीय व्यापार की सम्पूर्ण मात्रा 1175833 टन थीं । इसके विपरीत पिछले वर्ष यह संख्या 1,197,141 टन थी । 1964-65 में विदेशी व्यापार 3201007 टन था जो 1965-66 में बढ़ कर 3695759 टन हो गया ।

पोर्ट ट्रस्ट रेल ने 2831530 टन के यातायात का संचालन किया। पिछले वर्ष की यह संख्या 2516055 टन थी।

3 मौवहन :

वर्ष में पाल जहाजों को छोड़कर, पत्तन में आने वाले जहाजों की संख्या 1406 थी पिछले वर्ष यह संख्या 1343 थी। कुल टन भार 5,776,616 था। पिछले वर्ष यह संख्या 5463647 थी।

विचाराधीन वर्ष में 107941 यात्रियों ने पत्तन को व्यवहृत किया पिछले वर्ष की यह संख्या 94181 यात्री थी।

4. श्रम:

वर्ष के दौरान श्रम स्थिति सन्तोषजनक रही। श्रम कल्याण उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा।

5 निर्माणकार्य :

1. साउथ की -1 का पुनर्निर्माण पूर्ण होने के निकट था।
2. साउथ की-1 पर दो भंजसी परिवहन सायबान का निर्माण कार्य पूर्ण होने को था।
3. नाव द्रोणी को फिर से बनाने का कार्य पूर्ण होने को था।
4. वेस्ट डाक और वेस्ट की पर 17 नये फ्रेम लगाने और दो फ्रेमों को बदलने का काम जनवरी, 1966 में पूरा हो गया।
5. नाव द्रोणी के लिये बेस्कूलपुल पर निर्माणकार्य पूरा हो गया।
6. सेंटर बर्थ, वेस्ट की के कार्यालय और पारवहन सायबान का निर्माण पूरा हो गया।
7. फिलपौक शीफ्ट से पत्तन तक अलहुदा 21" मेन के डाले जाने का काम जुलाई, 1966 में पूरा कर दिया गया।

8. मार्शलिंगगार्ड पर नये वर्कशापों का निर्माण संबन्धी कार्य हाथ में ले लिया गया है और प्रगति हो रही है।

9. कर्मचारियों के लिये टाइप दो की 276 इकाइयों और टाइप 1 की 132 इकाइयों के मकानों का निर्माण प्रगति पर है।

6 विविध :

1. परीक्षण के आधार पर 1-4-65 से लोकोम के निर्गत में सुधार करने के लिए एक उत्प्रेरक योजना खलाई गई।
2. 1-5-66 से कर्मचारियों के कुछ वर्गों के लिये खाद्यान्न जहाजों से मास उतारने में सुधार करने के लिये एक इनाम योजना चालू की गई।
3. बोर्ड ने 1-3-1965 और 1-12-1965 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरों को और 1-7-1965 से घर किराया भत्ता को ट्रस्ट के कर्मचारियों के लिये, जैसी कि वे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती थी, क्रियान्वित किया।
4. 1-2-1965 से समस्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 7.80 रुपये प्रतिमास की अन्तरिम सहायता दी गई। यह पोर्ट और डाक कर्मचारियों के वेज बोर्ड के पंचाट पर आधारित थी।

अभिस्वीकार

पोर्ट ट्रस्ट मंडल ने उपयोगी कार्य का एक और वर्ष संपूर्ण किया। विचाराधीन वर्ष में मंडल द्वारा किये गये कार्य की सरकार सराहना करती है।

के. नरायनन, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

(Communications Division)

New Delhi, the 23rd December 1966

No. 5919-PTI/66.—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959 published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F. 3(40)-NS/58, dated the 19th December, 1958, namely :—

1. These rules may be called the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) (Third Amendment) Rules, 1966.

2. In the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959,—

(i) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely :—

"5. Amount of deposit.—

Deposits can be made of Rs. 5 or of any multiples thereof but not exceeding Rs. 300 subject to the limits specified in rule 7, provided that the amount of deposits made at the time of opening the account shall not be varied during the currency of the account."

(2) in sub-rule (2) of rule 6, for items (ii) to (vii) the following item shall be substituted, namely—

(ii) For an account of any other denomination specified in rule 5. 5 Paise for every Rs. 10 of the instalment plus 2 paise for fraction of Rs. 10 thereof, if any, for each month of default."

(3) In Table I, the following shall be inserted at the end, namely :—

"The maturity values for other denominations specified in rule 5 shall be in proportion to the maturity values set out above."

(4) in Table II, the following shall be inserted at the end, namely :—

"Proportionate amounts payable at the end of the term on the discontinuance of the account in respect of the other denominations specified in rule 5 shall be in proportion to the amounts set out above for an account of Rs. 5 denomination."

(5) the note below rule 8 shall be omitted.

(6) in Table IA and Table IB the following shall be inserted at the end of each Table, namely :—

"The maturity bonus for accounts of other denominations specified in rule 5 shall be in proportion to the maturity bonus set out above for monthly deposits of Rs. 5."

(7) in Table III, the following shall be inserted at the end, namely :—

"Cash values payable to the legal heir on the death of a depositor in a single account or to the survivor in a Joint Account in respect of the other denominations specified in rule 5 shall be in proportion to the cash values set out above in respect of an account with a monthly deposit of Rs. 5."

(8) in rule 10, in sub-rule (1), the Note below clause (c) shall be omitted.

C. B. GULATI, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 13th December 1966

No. 12/50/66-E.-Pty.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 133-V of the Defence of India Rules, 1962, the Central Government hereby orders that all moveable and immoveable properties in India belonging to, or held by, or managed on behalf of (1) Mrs. Kulsum Bai Kareem daughter of late Mr. Haji Mohomad Hajee Moosa Sait and late Mrs. Amna Bai Hajee Issa, formerly residing at Pattergatti, Hyderabad (Andhra Pradesh) and (2) Mrs. Zebeida Bai Osman Lathif, daughter of late Mr. Haji Mohamad Hajee Moosa Sait and late Mrs. Amna Bai Hajee Issa formerly residing at Snell Road, Ranavav (Gujarat State) and both now Pakistan nationals of Karachi, shall vest in the Custodian of Enemy Property for India.

V. K. AHUJA, Jr. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

New Delhi, the 21st December 1966

No. SSI(A)-17(2)/65.—In the Ministry of Industry Resolution No. SSI(A)-17(2)/65 dated the 18th May, 1966, under which the Small Scale Industries Board was reconstituted, the following amendment may be made, namely

In the list of members of the Small Scale Industries (official Level) Committee,

For "3. Adviser (Industries), Planning Commission".

Read "3. Dr. D. K. Malhotra, Joint Secretary, Planning Commission".

R. SUBRAMANIAN, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

RESOLUTION

New Delhi, the 21st December 1966

No. 15-27/66-LDI.—Poultry industry in India has made rapid progress in recent years. Comprehensive poultry development projects have been undertaken both by the Central and State Governments under the national Five Year Plans. Private enterprise has also made considerable contribution in this field. Increasing awareness regarding the high nutritive value of poultry products and the need for supplementing the average Indian diet with protective foods have greatly increased the demand for these products. In order to meet this increasing demand, birds of high genetic quality have to be produced in large numbers and maintained under scientific methods of feeding and management. This will necessitate provision of adequate marketing facilities. In order to ensure concerted and well-coordinated efforts, both in the private and public sectors, to tackle the problems that may arise in the implementation of various programmes undertaken to increase poultry production in the country, the Government of India have decided to set up a Central Poultry Development Advisory Council.

2. The Council has accordingly been constituted as under :—

Chairman

Minister of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation, Government of India.

Vice-Chairman

Deputy Minister food, Agriculture, Community Development & Cooperation, in-charge Animal Husbandry.

Members

1. Additional Secretary Incharge of Animal Husbandry in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation, Government of India.
2. Animal Husbandry Development Commissioner with the Government of India.
3. Livestock Development Adviser to the Government of India.
4. Agricultural Marketing Adviser to the Government of India.
5. Deputy Animal Husbandry Commissioner (Animal Health), Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation, Government of India.
6. Poultry Specialist, Directorate of Extension, Government of India.
7. One representative of the Planning Commission.
8. One representative of the Directorate General of Technical Development, Government of India.
- 9 to 12 Directors of Animal Husbandry or the Chief Poultry Specialists from four States, Union Territories; one from each region to be nominated by the Government of India for two years by rotation.
13. Deputy Director General (Animal Sciences), Indian Council of Agricultural Research.
14. Head of the Division of Poultry Research, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar.
15. One representative of the Central Food Technological Research Institute, Mysore.
16. One representative of the Indian Standards Institution.
17. One representative from large Commercial hatcheries.
- 18 & 19. Two representatives from cooperative societies engaged in poultry production.
- 20 to 23. Four private progressive poultry farmers, one from each region.
24. One representative from poultry equipment manufacturers.
- 25 & 26. Two representatives from poultry feed manufacturers—one each from large scale and small scale manufacturers.

Members at Serial Nos. 17 to 26 will be nominated by the Government of India.

Member-Secretary

Deputy Animal Husbandry Commissioner (Poultry), Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation, Government of India.

3. Government of India may nominate, from time to time, additional members to represent interests not already represented on the Council.

4. The council will be an advisory body and will have the following functions :—

- (i) to consider, from time to time, the Poultry Development Programmes formulated by the Central and State Governments;

- (ii) to consider and review the progress of Poultry Development Programmes in the context of targets laid down and to recommend measures for accelerating the tempo, wherever necessary;
- (iii) to consider and review the problems of poultry breeding, nutrition, disease control, technology, marketing, trade etc. including price policy and to make suggestions for improvement; and
- (iv) any other function, which may from time to time be assigned by the Government of India to the Council.

5. The Council will meet periodically at such time and place as may be decided by the Chairman.

6. The Council may, by Resolution, appoint Committees for advising it in connection with problems relating to Poultry Breeding, Feeds and Marketing, Disease Control, Equipment Manufacture and for any other purposes as it may think fit.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and the Departments of the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. J. MAJUMDAR, Additional Secy.

(Department of Food)

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd December 1966

No. 211(6)/65-PY.II.—Consequent on the constitution of an Advisory Committee on 1-10-1966 under section 11 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby rescind the Resolution of the Government of India in the Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No. 211(1)/64-PY.II dated 29th December, 1964 relating to the formation of the All India Committee of representatives of the trade in foodgrains.

T. S. BROCA, Dy. Secy.

(Department of Co-operation)

New Delhi, the 22nd December 1966

No. 1-5/66-G(Suppl. List 5).—In continuation of this Department Notification No. 1-5/64-G (Suppl. List 4) dated the 23rd November, 1966 the following Wholesale Cooperative Stores are added to the schedule of Cooperative Societies published along with the Notification No. 1-25/65-CC dated 27-5-66 regarding the Guarantee Scheme for Consumer Cooperatives.

1. The Cooperative Stores Ltd., Nampalli Road, Hyderabad (Andhra Pradesh).
2. The Damoh Wholesale Consumer Cooperative Store, Damoh (Madhya Pradesh).
3. Raigarh District Wholesale Consumer Cooperative Store Ltd., Raigarh (Madhya Pradesh).
4. Hoshangabad District Wholesale Consumer Cooperative Store Ltd., Fazil Mansion, Hoshangabad, (Madhya Pradesh).
5. District Wholesale Consumer Cooperative Store Ltd., Somwaria Bazar, Shajapur (Madhya Pradesh).
6. District Wholesale Consumer Cooperative Store Ltd., Dhar (Madhya Pradesh).
7. Dewas Sahakari Thok Upbhokta Bhandar, Agra-Bombay Road, Dewas (Madhya Pradesh).
8. The Mandsaur Central Wholesale Consumer Cooperative Ltd., Nai Abadi Mandsaur (Madhya Pradesh).
9. Guna District Cooperative Wholesale Store, Guna (Madhya Pradesh).
10. Wholesale Consumer Cooperative Store Ltd., Rewa (Madhya Pradesh).
11. Wholesale Consumer Cooperative Store Ltd. Satna (Madhya Pradesh).
12. Wholesale Consumer Cooperative Store Ltd. Shahdol (Madhya Pradesh).
13. Wholesale Consumer Cooperative Store Ltd., Bhind (Madhya Pradesh).
14. Khargone Wholesale Consumer Cooperative Store Ltd., Khargone (District West Nimar) Madhya Pradesh.
15. Pali Sahkari Upbhokta Wholesale Bhandar Ltd., Pali (Rajasthan).
16. Nagaur Sahkari Upbhokta Wholesale Bhandar Ltd., Nagaur (Rajasthan).
17. Bhilwara Sahkari Upbhokta Wholesale Bhandar Ltd., Bhilwara (Rajasthan).
18. Bharatpur Sahkari Upbhokta Wholesale Bhandar Ltd., Bharatpur (Rajasthan).
19. Tonk Sahkari Upbhokta Wholesale Bhandar Ltd., Tonk (Rajasthan).

CORRIGENDUM

No. 1-5/66-G.—Read “B. N. K. Sahkari Upbhokta Wholesale Bhandar Ltd., Beawer (Ajmer-Rajasthan)” for “B. N. K. Sahakari Wholesale Upbhokta Bhandar Champanagar, P.O. Bewar (Rajasthan)” and also “Sikar Wholesale Sahakari Upbhokta Bhandar Ltd., Sikar (Rajasthan)” for “Sikar Sahakari Upbhokta Bhandar P.O. Sikar, District Sikar (Rajasthan)” at Serial Nos. 24 and 26 respectively in Notification No. 1-5/66-G dated the 29th September 1966, appearing on page 686 and 687 of the Gazette of India, Part I Section 1, dated October 15, 1966 (Asvina 23, 1888).

V. V. NATHEN, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

RESOLUTION

New Delhi, the 21st December 1966

No. 14/2/66-SCT.II.—In continuation of the Department of Social Welfare Resolution No. 14/2/66-SCT.II, dated the 9th November, 1966, the Government of India hereby extend the term of the Committee on Untouchability, Economic Uplift and Educational Development of Scheduled Castes for a further period of six months upto 30th June, 1967.

2. Shri N. Sundaram, Director, Backward Classes Welfare, Department of Social Welfare, is appointed as Member-Secretary of the Committee.

Shri S. K. Kaul will cease to function as Secretary of the Committee.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MIR NASRULLAH, Dy. Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT AND AVIATION

(Department of Transport and Shipping)

(Transport Wing)

PORTS

RESOLUTION

New Delhi, the 21st December 1966

No. 13-PG(66)/66.—The Government of India have received the Administration Report of the Port of Madras for the Year 1965-66. The following are the noteworthy features in the Report :—

1. FINANCIAL POSITION

The actual net revenue receipts of the Port Trust for the year under review amounted to Rs. 538.64 lakhs as against Rs. 444.77 lakhs in the previous year.

The net expenditure for the year, including debt charges amounted to Rs. 436.20 lakhs as against Rs. 376.85 lakhs during the previous year. The increase in expenditure was mainly under Dock Establishment and Railway Department.

During the year under review, the Port Trust contributed a sum of Rs. 20 lakhs to its Capital Account, Rs. 37.74 lakhs to the Renewals and Replacements Fund and Rs. 1 lakh to the General Insurance Fund.

The receipts and expenditure of the Pilotage Fund amounted to Rs. 10.60 lakhs and Rs. 11.98 lakhs respectively. The expenditure included a contribution of Rs. 3 lakhs to the Revenue Account. Excluding this contribution of Rs. 3 lakhs, the result of working showed a surplus of Rs. 1.62 lakhs. The closing balance in the account at the end of 1965-66 was Rs. 1.71 lakhs.

The balances in the various Reserve Funds at the end of the year amounted to Rs. 3.16 crores. Besides, there was a closing balance of Rs. 102.26 lakhs in the Revenue and Pilotage Account.

Outstanding Loans

(i) The total amount of loan due to the Government of India as outstanding at the end of the year under review was Rs. 5.34 crores.

(ii) A sum of Rs. 33.43 lakhs was drawn from the International Bank for Reconstruction and Development during the year, bringing the total amount of the loan drawn upto the 31st March, 1966, to Rs. 4.77 crores.

2. TRAFFIC

There was a general increase in the volume of trade passing through the port during the year. The figures of dead weight tonnage of imports and exports which passed through the port during the year were 3,298,879 and 1,572,713 respectively. The corresponding figures for the previous year were 2,992,865 tonnes (Imports) and 1,403,283 tonnes (Exports). The increase in imports was due to a sharp rise in the import of foodgrains, chemical manures and phosphates. Imports of machinery, iron and steel and other Metals also showed an appreciable increase. The increase was partially off-set by the decline in import of coal. Exports during the year showed a rise, on account of considerable increase in the export of iron ore, bunkers and molasses. This was partially off-set by a sharp decline in the export of manganese ore.

The total volume of coastal trade for the year 1965-66 was 1,175,833 tonnes as against 1,197,141 tonnes in the previous year. Foreign trade rose from 3,201,007 tonnes in 1964-65 to 3,695,759 tonnes in 1965-66.

The Port Trust Railway handled a traffic of 2,831,530 tonnes as against 2,516,055 tonnes last year.

3. SHIPPING

The number of ships, excluding sailing vessels, that entered the port during the year was 1406 as against 1343 in the previous year. The net tonnage was 5,776,616 as against 5,463,647 during the previous year.

During the year under review 1,07,941 passengers used the port as against 94,181 passengers in the previous year.

4. LABOUR

The labour situation during the year was satisfactory. Labour Welfare measures continued to receive special attention.

5. WORKS

- (i) The reconstruction of South Quay-1 was nearing completion.
- (ii) The work of construction of a double storeyed Transit shed at South Quay-1 was nearing completion.
- (iii) Work on remodelling the Boat Basin was nearing completion.
- (iv) The work of installing 17 new and replacing 2 cranes at the Wet Dock and West Quay was completed in January 1966.
- (v) The work on the Bascule Bridge for Boat Basin was completed.
- (vi) Construction of Transit shed and offices at Centre Berth, West Quay was completed.
- (vii) The work of laying a separate 21" main from Kilpauk Shaft to the Port was completed in July, 1965.
- (viii) The work regarding construction of New Workshops at marshalling yard was taken in hand and was in progress.
- (ix) Construction of 276 units of type II and 132 units of type I staff quarters was in progress.

6. MISCELLANEOUS

(i) An incentive scheme was introduced to improve the output of locos with effect from 1-4-65 on a trial basis.

(ii) A prize scheme for improvement of discharge from foodgrain vessels effective from 1-5-65 to certain categories of employees was introduced.

(iii) The Board implemented the revised rates of Dearness Allowance with effect from 1-3-1965 and 1-12-1965 and House Rent Allowance with effect from 1-7-1965, respectively to the Trust's employees as applicable to the Central Government Employees.

(iv) An interim Relief of Rs. 7.80 per mensem based on the award of the Wage Board for Port and Dock Workers was also granted to all Class III and IV employees with effect from 1-2-1965.

Acknowledgement

The Port Trust Board performed another year of useful work and Government view with appreciation the work done by the Board during the year under review.

K. NARAYANAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 17th December 1966

No. E(G)65LL2-54.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 48 of Order XXI of the First Schedule to the Code of Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) No. E(G)62LL2-37 dated the 28th June, 1963, as amended vide their notification No. E(G)65LL2-54 dated 14-7-66, namely :—

In column (1) of the Table annexed to the said notification for sub-items (a), (b) (c) and (d) of item 2, the following shall be substituted, namely :—

- “(a) Deputy Director General, Research Designs and Standards Organisation, Lucknow.
- (b) Deputy Director (Establishment), Research Designs and Standards Organisation, Lucknow.”

P. C. MATHEW, Secy. Railway Board,

MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

RESOLUTION

New Delhi, the 16th December 1966

No. 21011(3)/66-UD.—In order to secure the collaboration of the Governments of Uttar Pradesh and the erstwhile Punjab in the formulation and implementation of the Master Plan for the Delhi Metropolitan Region, the Government of India had set up a High Powered Board, vide the Ministry of Health Resolution No. F.10-79/60-LSG, dated the 31st July, 1961. The terms of reference to the Board were as follows :—

- (1) To ensure that co-ordinated plans are prepared for the metropolitan area (including the Ring Towns) and, if necessary, also for the National Capital Region, through the agencies under the administrative control of each of the Governments participating;
 - (2) To ensure the provision of adequate funds for the preparation and implementation of the plans on a phased and integrated basis so that the development is balanced over the whole area on the basis of the accepted proposals in the plan or plans;
 - (3) To guide the various agencies for the implementation of the plans in the different areas;
 - (4) To consider any proposals that may come up from time to time from the various planning agencies in the different areas for the modification of the plan according to changing needs and circumstances.
2. Consequent on the reorganisation of the erstwhile Punjab and the recent administrative changes in the Union Territory of Delhi, the Government of India have decided to revise the constitution of the High Powered Board which will now be as follows :—

Chairman

- (1) Minister of Home Affairs, Government of India.

Members

- (2) Minister of Works, Housing and Urban Development, Government of India.
- (3) Minister of Health and Family Planning, Government of India.
- (4) Deputy Chairman, Planning Commission.
- (5) Chief Minister of Uttar Pradesh.
- (6) Chief Minister of Haryana.
- (7) Mayor of Municipal Corporation of Delhi.
- (8) Lt. Governor of Delhi.
- (9) The Chief Executive Councillor Delhi.

Member-Secretary

- (10) Joint Secretary, Ministry of Works, Housing and Urban Development, Government of India.

3. The terms of reference of the Board will remain unchanged.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. PRASADA, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

RESOLUTION

New Delhi, the 16th December 1966

No. WB-13(11)/66.—A Central Wage Board for the leather and leather goods industry was constituted by the

Government of India by their Resolution No. WB-19(2)/65 dated the 21st March, 1966. The Wage Board has made recommendations, as shown in the appendix, for grant of Interim Relief.

2. Government have decided to accept the recommendations of the Wage Board and to request the concerned employers to implement the same as early as possible.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

Unanimous Decision of the Central Wage Board for Leather and Leather Goods Industry on the Grant of Interim Relief

At the Meeting of the Central Wage Board for Leather and Leather Goods Industry held at No. 5, Venkatanarayana Road, T. Nagar, Madras, on the 28th October, 1966, under the Chairmanship of Shri M. Sriramamurty, it was unanimously decided to recommend the grant of Interim Relief to the Workers in the Leather and Leather Goods Industry as follows :

"The workers getting as on 1st October 66, wages (i.e. basic plus D.A., or a consolidated wage), in the wage range mentioned in items, in column 1 below, be paid Interim Relief as shown against each item in column 2 below :—

Column 1

Column 2

- | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Upto and inclusive of Rs. 75 p.m. | Rs. 12.50 p.m., subject to limitation that no worker gets as a result of this recommendation more than Rs. 85 p.m. |
| 2. Above Rs. 75 p.m., but not more than Rs. 150 p.m. | Rs. 6 p.m., subject to a minimum of Rs. 85 p.m. |
| 3. Above Rs. 150 p.m. and upto Rs. 500 p.m. | Rs. 5 p.m., subject to a minimum of Rs. 156 p.m. |

The above shall be subject to the following terms :

- (i) The Interim Relief shall take effect from 1-10-66.
- (ii) The Interim Relief which is only *ad hoc* will be in force till adjusted against the final recommendations of the Wage Board."

M. SRIRAMAMURTY,

Chairman

Central Wage Board for Leather and Leather Goods Industry.

Members

1. Shri T. Jiyar Das.
2. Dr. D. L. Narayana.
3. Shri Haji Mohamed Sami.
4. Shri A. Mohd. Ghouse.
5. Shri Sailen Paul.
6. Shri Ramanand Das.

V. S. SUNDRAM

Secretary

Central Wage Board for Leather and Leather Goods Industry.